

पाकिस्तान में 18 बस यात्री अगवा, सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों का आतंक, फायरिंग में कई घायल

नई दिल्ली : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक बस पर हमला कर 18 यात्रियों का अपहरण कर लिया। यह बस सिंध से बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की ओर जा रही थी। यह गंभीर घटना सोमवार रात

घोटकी इलाके के पास, सिंध-पंजाब सीमा के करीब हाईवे लिंक रोड पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हथियारबंद हमलावरों ने पहले बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसके बाद उन्होंने बस को रुकवाया और पुरुष यात्रियों को



नीचे उतारकर बंधक बस चालक और कुछ बना लिया। गोलीबारी में यात्री घायल हो गए,

जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार एक महिला यात्री ने बताया कि मौके पर 18 से 20 हमलावर मौजूद थे। सभी हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे और वे भारी हथियारों से लैस थे। महिला यात्री के

मुताबिक, हमलावरों ने करीब 25 यात्रियों को बस से उतरने के लिए कहा, लेकिन महिलाओं को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाई गई। सिंध के गृह मंत्री के प्रवक्ता जिया उल हसन लांझर ने बताया कि ड्राइवर और खलासी

के अलावा बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां घटना की जांच कर रही हैं और अपहृत यात्रियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा

व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालांकि, अभी तक किसी भी समूह ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला एक बार फिर सिंध और बलूचिस्तान को जोड़ने वाले मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

ऑस्ट्रेलिया में हमला करने वाला भारतीय निकला, हैदराबाद का रहने वाला था साजिद अकरम



नई दिल्ली ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदी लोगों पर हमला करने वाला आतंकी को लेकर बड़ा खुलासा

हुआ है। हमला करने वाला 50 वर्षीय आतंकी साजिद अकरम भारत का रहने वाला था। तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के

बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी का संदिग्ध साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था, जो 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया

था। साजिद और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम ने रायफलों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसे ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। साजिद पुलिस के साथ गोलीबारी में मारा गया, जबकि नवीद गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में पुलिस हिरासत के तहत रखा गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों की कट्टरपंथी विचारधारा का भारत या तेलंगाना से कोई संबंध नहीं है। घटना के बारे में तेलंगाना पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम का परिवार हैदराबाद में रहता है, लेकिन उनके साथ उनका संपर्क बहुत सीमित था। साजिद ने ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भारत की छह बार यात्रा की थी, लेकिन उनके परिवार को उनकी कट्टर सोच के बारे

मोदी के ड्राइवर बने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस, खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए



नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे के दौरान उनकी खास तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्राइवर बन गए। एक खास अंदाज में क्राउन प्रिंस मंगलवार को पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से गाड़ी चलाकर जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। क्राउन प्रिंस, पैगंबर मोहम्मद के 42वां पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज हैं। वह संग्रहालय भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरे समय मौजूद रहे। जॉर्डन म्यूजियम की यह यात्रा अम्मान में प्रधानमंत्री मोदी के व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा रही। विदेश मंत्रालय के अनुसार, जॉर्डन म्यूजियम का दौरा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का एक अहम पड़ाव था। विदेश मंत्रालय में सचिव (दक्षिण) डाक्टर नीना मल्होत्रा ने विशेष ब्रीफिंग में बताया था

कि क्राउन प्रिंस के साथ पीएम मोदी म्यूजियम का दौरा करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, जल प्रबंधन, संस्कृति और लोगों के आपसी संपर्क से जुड़े कई समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया, जहां

कि रेन्वेबल एनर्जी से लेकर डिजिटल इनोवेशन तक हुए समझौते दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी की गहराई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जॉर्डन की व्यापारिक बिरादरी को भारत में निवेश करने के लिए हड़ता से आमंत्रित किया। भारत-जॉर्डन बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को 8 प्रतिशत से अधिक की गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हुए निवेशकों को उत्कृष्ट रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने जॉर्डन की कंपनियों को भारत की इस विकास यात्रा का साझेदार बनने का सुनहरा मौका लेने के लिए प्रेरित किया।

कश्मीर में आतंक पर प्रहार, आतंकी मामले में सीआईके की कार्रवाई, घाटी में 12 जगहों पर मारे छापे



श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने मंगलवार को एक आतंकी मामले के सिलसिले में कश्मीर घाटी में 12 जगहों पर छापे मारे।

अधिकारियों ने बताया कि सीआईके पुलिस स्टेशन में 2023 में आईपीसी की धारा 153-ए और 505 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की

धारा 13 और 18 के तहत दर्ज मामले में तलाशी वारंट मिलने के बाद सात जिलों में 12 जगहों पर तलाशी ली गई। यह मामला आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों और आतंकवाद के ऑनलाइन समर्थन से संबंधित है, जिसका मकसद कथित तौर पर चरमपंथी गतिविधियों के लिए लोगों की भर्ती करना था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का मंगलवार को आदेश दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेका) के नेता चौधरी ने इस मामले में स्थायी व अनिवार्य रोक लगाए जाने का अनुरोध किया है। जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र

नई दिल्ली विपक्ष के विरोध के बीच सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन विधेयक) 2025 मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इसे संविधान विरोधी बताते हुए इसे पेश नहीं किए जाने की मांग की। रिजोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि पहले ही बीमा संशोधन में इतने संशोधन किए गए हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार को बताना चाहिए कि किस प्रयोजन से इसे सदन में रखा जा रहा है। बिल का शीर्षक ऐसा होना चाहिए, जिससे विधेयक के प्रावधान पता चले। क्या यह विधेयक शत प्रतिशत लोगों की मदद कर रहा है। इससे



एलआईसी एजेंटों की संख्या कम की गई है। यह लोगों के हित में नहीं है। द्रमुक की टी सुमति ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के साथ-साथ देश

की अखंडता के खिलाफ है। यह राष्ट्रहित में नहीं है। इस विधेयक से बीमा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी को दिक्कतें आ सकती हैं। टीएमसी के सीत राय ने कहा कि यह विधेयक का

हिंदीकरण का उदाहरण है। इससे हिंदी को स्थापित किया जा रहा है। विधेयक का नाम नारे के रूप में नहीं होना चाहिए। अब बीमा क्षेत्र सौ प्रतिशत विदेशी कंपनियों को देने का प्रावधान किया जा

रहा है जिससे कॉरपोरेट को फायदा होगा। विपक्ष के विरोध पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि विधेयक की पुरःस्थापना के समय ऐसे विषय उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर चर्चा में सभी विषयों को उठाया जाना चाहिए। जो बिंदु उठाए गए हैं वह चर्चा के विषय हैं। एलआईसी एजेंटों का कमिशन पहले से निर्धारित है इसमें कोई नई बात नहीं है। यह आम नागरिकों को सर्वव्यापक स्तर पर बीमा प्रदान करेगा। विपक्ष का इसे कल्याणकारी योजना के खिलाफ बताना सही नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को राज्यसभा में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं जैसी महिला कर्मियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए उनका मानदेय बढ़ाने जाने की मांग की।

मोदी ने भारत-जॉर्डन सहयोग की सराहना की, पांच प्रमुख समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

अम्मान। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जॉर्डन की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान पांच समझौतों पर हस्ताक्षर होने पर इनकी सराहना करते हुए इसे भारत-जॉर्डन साझेदारी का ह्रस्वार्थक विस्तार कह बताया। दोनों देशों के बीच जिन पांच समझौतों पर हस्ताक्षर हुये हैं, उनमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन और विकास में सहयोग, विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए

पेट्रा और एलारा के बीच एक समझौता, 2025-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के नवीनीकरण से संबंधित समझौते शामिल हैं। जिससे लोगों के आपसी संपर्क को और बढ़ावा दिया जाएगा और डिजिटल परिवर्तन के लिए भारत के सफल डिजिटल समाधानों को बड़े पैमाने पर साझा करने से संबंधित समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरे के महत्व पर कहा कि ये समझौते भारत-जॉर्डन

जॉर्डन संबंधों की बढ़ती गहराई और व्यापकता को दर्शाते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हूनवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग स्वच्छ विकास, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु जिम्मेदारी के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, हूजल संसाधन प्रबंधन में सहयोग से हमें संरक्षण, दक्षता और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने का अवसर

मिलेगा, जिससे दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रा और एलारा के बीच समझौता शैक्षणिक आदान-प्रदान, विरासत संरक्षण और पर्यटन संवर्धन के नए अवसर खोलेगा, जबकि सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण भारत और जॉर्डन के लोगों के बीच गहरे संबंधों को बढ़ावा देगा। भारत के डिजिटल नवाचारों को साझा करने से जॉर्डन के

डिजिटल परिवर्तन को समर्थन मिलेगा और समावेशी शासन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का अल हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बातचीत में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, कृषि, बुनियादी

ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे विषय शामिल रहे। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दोहराई। अम्मान स्थित अल हुसैन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भारत-जॉर्डन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भारत की ओर से समर्थन देने की घोषणा भी की गई, जो तीन वर्षों में 10 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करेगा और शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग को मजबूती प्रदान करेगा।



संपादकीय

संपादक - मृतुजा भाग्यजीवाला

गांधी परिवार को राहत

राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यु अदालत ने ह्वनेशनल हेराल्ड केसह्म में आरोप-पत्र का संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। आरोप-पत्र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दाखिल किया था। सालों की जांच-पड़ताल, साक्ष्यों के संग्रह और आरोपितों से सवाल-जवाब के बाद यह आरोप-पत्र तैयार किया गया था। अदालत का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज किए बिना किसी आरोप-पत्र पर संज्ञान लेना संभव नहीं है, क्योंकि पूरी जांच एक निजी शिकायत के आधार पर की गई है। वह निजी शिकायत 2012 में डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दर्ज कराई थी। यदि यह तर्क उचित है, तो इतने लंबे सालों तक सरकारी जांच एजेंसियां जांच क्यों करती रहीं? गौरतलब यह है कि 2019 में ह्यधनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में यह संशोधन किया गया था कि जांच एजेंसी निजी शिकायत के आधार पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर सकती है, लिहाजा वह अदालत में आरोप-पत्र भी दाखिल कर सकती है। ऐसे संसदीय संशोधन के बावजूद निचली अदालत ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? बहरहाल इस सवाल पर ईडी उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है, लेकिन निचली अदालत ने केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की और जांच को जारी रखने के आदेश दिए। बेशक सोनिया-राहुल गांधी के लिए फिलहाल एक बड़ी राहत है, क्योंकि अदालत में आरोप तय नहीं होंगे, तो केस कैसे चलेगा? गांधी द्वय को सजा भी नहीं दी जा सकती। घोटाले का यह केस किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। ह्वनेशनल हेराल्ड केसह्म गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उसे 2000 करोड़ रुपए के घपले के तौर पर चित्रित किया जाता रहा है। सोनिया-राहुल गांधी को अभियुक्त नंबर 1 और 2 बनाया गया है।

2000 करोड़ रुपए का आरोप न तो ईडी का है और न ही किसी अदालत में साबित हुआ है। ईडी ने भी करीब 900 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे 359 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला बताया था। तो फिर 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से उदित हुआ है? ह्वनेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में जवाहर लाल नेहरू ने शुरू किया था। ह्यएसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कंपनी बनाई गई थी, जिसके शेयर नेहरू के अलावा, 5000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों ने भी खरीदे थे। उसे ह्यआजादी का मुखपत्रह्म बनाने की कोशिशें थीं। मौजूदा संदर्भ में एजेएल के तमाम शेयर ह्ययंग इंडियन लिमिटेडह्म को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जिसके 38-38 फीसदी (कुल 76 फीसदी) शेयर सोनिया-राहुल गांधी के नाम हैं। कंपनी एक्ट की धारा 25 के तहत पंजीकृत यह कंपनी ऐसी है, जिसमें कोई वेतन, लाभांश आदि नहीं लिया जा सकता। एजेएल की तमाम संपत्तियां लीज के तहत हैं, लिहाजा उन्हें बेचा नहीं जा सकता। संपत्तियों से 60 लाख रुपए का किराया दिखाया गया है। वह पैसा कहां जाता है, इस पर भी एजेंसी के सवाल हैं। यह मामला 2016 में सर्वोच्च अदालत में भी गया था, लेकिन अदालत ने गंभीर आपराधिक आरोपों के मद्देनजर कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया। दिसंबर, 2015 में सोनिया-राहुल गांधी को ह्यपटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी। ईडी 2014 से जांच शुरू कर चुका था। सवाल है कि प्राथमिकी और आरोप-पत्र के अंतर्संबंधों का उल्लेख किसी ने भी क्यों नहीं किया? आरोप-पत्र के बिना गांधी परिवार ह्यआरोपितह्म कैसे करार दिया गया और जमानत किस आधार पर दी गई? कोई तो वजह होनी चाहिए कि जिसके आधार पर किसी को घोटाले का आरोपी कहा जाए? अब ऐसे सवाल नए सिरे से उठेंगे। आयकर, सीबीआई, ईडी सभी प्रमुख जांच एजेंसियां जांच कर चुकी हैं।

उनके बावजूद दिल्ली पुलिस की ह्यआर्थिक अपराध शाखाह्म ने बीती 3 अक्टूबर को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। तो इससे पहले की जांच एजेंसियों के तात्कालिक निष्कर्ष किन कानूनी धाराओं के तहत थे? नतीजतन अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक दुर्भावना, दुष्प्रचार करने और गांधी द्वय पर कानूनी दबाव बनाए रखने का मामला बता रही है। भाजपा इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का संकल्प दोहरा रही है। क्या अब यह मामला नए सिरे से उठेगा अथवा उच्च अदालत हस्तक्षेप करेगी, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। वैसे जहां तक कांग्रेस का संबंध है, वह इसे राजनीतिक रंजिश का केस बताती है। उसका कहना है कि मोदी सरकार उन लोगों को सहन नहीं करती है, जो उसकी जनविरोधी नीतियों की खिलाफत करते हैं। इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर यह केस चलाया गया है, जबकि इसमें गड़बड़ वाली कोई बात नहीं है। दूसरी ओर भाजपा इसे धोखाधड़ी बताती है।

भारतीय रुपए में गिरावट चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय रुपया हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। 11 दिसंबर 2025 को यह 90.51 के स्तर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले के 84.85 के स्तर से करीब 7 फीसदी की गिरावट दर्शाता है। यह गिरावट केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है। अमेरिकी टैरिफ, विदेशी निवेश में कमी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण रुपया दबाव में है। रुपए की गिरावट का एक काला अतीत भी है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.63 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसी बीच भारत के आर्थिक इतिहास के एक और भी बुरे दौर की यादें ताजा हो गई हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जो भारत को करेंसी शॉक का सामना करना पड़ रहा है। भारत को सबसे बड़ा झटका 1991 में लगा था, जब देश दिवालिया होने की कगार पर था। उस साल रुपए का संकट इतना गहरा था कि भारत को बचने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। 1991 में भारत ने अपने अब तक के सबसे बुरे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स संकट का सामना किया। विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक रूप से कम हो गया था। यह तेल और भोजन जैसे जरूरी आयात के लिए भी मुश्किल से दो या तीन हफ्तों के लिए ही बचा था। अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं का भरोसा खत्म हो चुका था। क्रेडिट रेटिंग्स गिर चुकी थी और भारत अपने बाहरी कर्ज की देनदारी पर डिफॉल्ट करने के करीब था।



इस संकट की जड़ें सालों से गलत तरीके से आर्थिक प्रबंधन करने के साथ-साथ वैश्विक झटकों में थी। भारत जीडीपी के 8 फीसदी से ज्यादा का भारी राजकोषीय घाटा चला रहा था। उसी समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था। 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ा दिया था, जिस वजह से भारत का आयात बिल बढ़ गया। इसी के साथ मध्य पूर्व में काम करने वाले भारतीयों से आने वाला पैसा भी कम हो गया। 1989 और 1991 के बीच राजनीतिक अस्थिरता ने विदेशी निवेशकों को और भी ज्यादा डरा दिया, जिस वजह से पूंजी पलायन हुआ। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मई और जुलाई 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास लगभग 67 टन सोना गिरवी रखा। इस कदम से भारत को आपातकालीन फंड के रूप में लगभग \$600 मिलियन जुटाने में मदद मिली। उस समय सोने की कड़ी सुरक्षा के बीच देश से बाहर ले जाया गया था। सरकार के इस कदम ने भारत को पूरी तरह से डिफॉल्ट होने से रोक दिया था।

सोना गिरवी रखने के साथ-साथ भारत ने वित्तीय सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट पैकेज देने पर सहमत हो गया, लेकिन उसने कड़ी शर्तें लगाईं। इनमें संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन, व्यापार उदारीकरण और मुद्रा का डीवैल्युएशन शामिल था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह की लीडरशिप में ऐतिहासिक सुधार हुए। भारत ने लाइसेंस राज को खत्म किया, आयात शुल्क कम किए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए दरवाजे खोले और साथ ही खुद को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिलाया। आइये रुपए की इस गिरावट के चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करें। रुपया और डॉलर का रेट तय होने का भी एक बाजार है, जिसे फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। यहां बैंक, बड़ी कंपनियां और निवेशक डॉलर खरीदते-बेचते हैं। जब डॉलर की मांग ज्यादा होती है और बाजार में डॉलर कम मिलते हैं, तो डॉलर महंगा और रुपया सस्ता हो जाता है। भारत ज्यादा आयात करे और निर्यात कम हो, तो हमें डॉलर में

ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, मांग बढ़ती है और रुपया टूटता है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची हों, तो विदेशी निवेशक वहां पैसा लगा देते हैं, भारत से डॉलर निकलते हैं और रुपया कमजोर होता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ें तो भी भारत को ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, इससे भी रुपया दबाव में आता है। निर्यात, विदेशी निवेश, एनआरआई की रেমिटेंस वगैरह के जरिये अगर भारत में ज्यादा डॉलर आते हैं तो रुपया मजबूत होता है। इसकी उलट स्थिति यानी ज्यादा आयात, विदेशी निवेशकों का भारतीय कंपनियों से निवेश वापस खींचने जैसी स्थितियों में रुपया कमजोर होता है। भारत पेट्रोल-डीजल और रसोई के तेल से लेकर मोबाइल, टीवी, मशीनरी जैसे सामानों और बहुत कुछ का आयात करता है। रुपया कमजोर होते ही इन्हें खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इसलिए पेट्रोल-डीजल, गैस, हवाई टिकट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपोर्टेड दवाएं और गाड़ियां महंगी होने लगती हैं। जब ईंधन महंगा होता है तो जाहिर है कि ट्रक-ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है और फिर उसका असर सब्जी, अनाज, दूध, पैकेज्ड

फूड जैसी रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों की कीमत पर भी पड़ता है, यानी महंगाई बढ़ती है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई, इलाज या घूमने के लिए विदेश जाने वालों पर असर और साफ दिखता है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, टिकट सब डॉलर में तय होते हैं, इसलिए रुपया गिरने पर सेम कोर्स की फीस, भारतीय परिवारों को लाखों रुपए ज्यादा लगती है। विदेश से ऑनलाइन शॉपिंग, ऐप सब्सक्रिप्शन जैसी सेवाएं भी धीरे-धीरे महंगी लगने लगती हैं। रुपया गिरने से सभी को नुकसान ही नहीं होता, कुछ निर्यातकों को फायदे भी होते हैं। जो कंपनी या एक्सपोर्टर विदेश में सामान बेचते हैं, उन्हें अगर डॉलर में पेमेंट मिलता है, तो वे रुपया गिरने की स्थिति में भी फायदे में होते हैं। विदेशों से पेमेंट में मिले डॉलर को जब वे रुपए में बदलते हैं तो उन्हें पहले से ज्यादा रुपए मिलते हैं। टेक्सटाइल, आईटी सर्विस, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर को इसमें थोड़ी बढ़त मिलती है। भारतीय रुपए में मौजूदा गिरावट के पीछे कई बड़े कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें वैश्विक आर्थिक स्थितियां और घरेलू कारक शामिल हैं। रुपए की गिरावट के कारणों,

भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों और क्या यह चिंता का विषय होना चाहिए, इस बार भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप भी काफी कम रहा है, जिससे गिरावट और तेज हुई है। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और बाजार को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक करेंसी को स्थिर करने के लिए कुछ कदम उठाएगा। तकनीकी रूप से रुपया बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य करेंसी की वैल्यू घटने को मुद्रा का गिरना, टूटना या कमजोर होना कहते हैं।

इसे अंग्रेजी में करेंसी डेप्रिसिएशन कहा जाता है। लंबी अवधि में विदेशी निवेशकों के लिए रुपए का गिरना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे उनकी रिटर्न रुपए में बदलने पर बढ़ जाती है। लेकिन निकट अवधि में दबाव बना रह सकता है। वैश्विक वित्तीय हालात, महंगा आयात और व्यापार से जुड़ी चुनौतियां रुपए को कमजोर बनाए रख सकती हैं। हकीकत यह है कि महंगाई के आंकड़े कुछ भी कहें वास्तविक जीवन में महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। निर्यात करने वालों को जरूर डॉलर में पैसे मिलने से फायदा हो रहा है, लेकिन वह फायदा तो चुनिंदा लोगों को है। हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, जिसका उपयोग वह अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए करता है। इस रिजर्व के घटने या बढ़ने का असर करेंसी की कीमत पर सीधा दिखता है। यदि भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर, अमेरिका के रुपए के भंडार के बराबर होगा, तो रुपए की कीमत स्थिर रहेगी। लेकिन यह नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर है।

आबुधाबी में आईपीएल मिनी ऑक्शन आज, 350 खिलाड़ि की किस्मत का होगा फैसला

आबुधाबी। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से आबुधाबी में शुरू होगा। 10 टीमों के पास 237.55 करोड़ रुपए का पर्स है। नीलामी में 350 प्लेयर्स उतरेंगे, लेकिन 77 ही बिक पाएंगे, क्योंकि टीमों में इतनी ही जगह खाली है। 40 प्लेयर्स की बेस प्राइस सबसे ज्यादा दो करोड़ रुपए है, वहीं 227 प्लेयर्स की बेस प्राइस सबसे कम 30 लाख रुपए है। आईपीएल मिनी ऑक्शन में अक्सर टीमों कुछ खिलाड़ि ों



पर बहुत ज्यादा रकम में छह खिलाड़ी ऐसे खर्च कर देती हैं। इतिहास रहे, जिन्हें टीमों ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत देकर खरीदा।

वहीं, ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत पिछले साल मेगा ऑक्शन में बिके। उन्हें 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपरजायंट्स ने खरीदा था। इस बार भी मल्लिका सागर ही ऑक्शनर रहेंगी। ऑक्शन के लिए दुनियाभर के 1390 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि, टीमों ने इनमें से कुछ ही प्लेयर्स चुने और उन्हें खरीदने में इंटेरेस्ट दिखाया। इसलिए ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने टॉप 350 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है।

मथीशा मालामाल, 18 करोड़ में केकेआर ने अपनी टीम में किए शामिल

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियम लिविंगस्टन को छप्पर फाड़ पैसा मिला है। लिविंगस्टन को सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने खरीदा। लिविंगस्टन को खरीदने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपए चुकाए। पिछले सीजन लिविंगस्टन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का हिस्सा थे और टीम आईपीएल चैंपियन भी बनी थी। लिविंगस्टन हालांकि अपनी काबिलीयत के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को आईपीएल 2026 की ऑक्शन में छप्परफाड़ पैसा मिला। इंग्लिस को लखनऊ सुपरजायंट्स ने 8.6 करोड़ रुपए में खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया का ये विकेटकीपर आईपीएल 2026 में सिर्फ चार ही मैचों के लिए उपलब्ध रहने वाला है। इसके बावजूद उन्हें इतनी बड़ी कीमत मिली है।



जोश इंग्लिस की आईपीएल 2026 के दौरान ही शादी है। वह ऑक्शन में आने से पहले ही बता चुके हैं कि वह चार मैच ही खेलेंगे। इसके बावजूद लखनऊ ने उनपर बहुत बड़ा

दांव खेल दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए की बड़ी राशि के साथ अपने स्क्वाड में शामिल किया।

वरुण चक्रवर्ती, तिलक वर्मा आईसीसी पुरुष टी-20 प्लेयर रैंकिंग में चमके

भारत के आक्रामक बल्लेबाज तिलक वर्मा आईसीसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय टी-20 प्लेयर रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी रैंकिंग में 818 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर जारी ताजा रिपोर्ट में तिलक वर्मा ने पिछले हफ्ते कटक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में 26 रन बनाने के बाद न्यू चंडीगढ़ में 62 और धर्मशाला में 26 रन बनाकर भारत के अभिषेक शर्मा की अगुवाई



वाली सूची में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और इंग्लैंड के जोस बटलर को पीछे छोड़कर वह अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में दो पायदान ऊपर चढ़ कर 774 अंकों के

चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को एक पायदान का नुकसान हुआ है वह 669 अंकों के साथ दसवें स्थान पर आ गए

हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा 909 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम की तीसरे मैच में सिर्फ 117 रन के स्कोर में 61 रन की पारी ने उन्हें आठ स्थान ऊपर 29वें स्थान पर पहुंचा दिया है, जबकि किंवटन डी कॉक की दूसरे टी-20 में मैच जिताने वाली 90 रन की पारी ने उन्हें 14 पायदान ऊपर उठाकर 53वें स्थान पर पहुंचा दिया है। टी-20 गेंदबाजी रैंकिंग की बात की जाए तो पिछले हफ्ते खेले गए दो टी-20 में दो-दो विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती ने अपने

खाते में 36 रेटिंग अंक जोड़े कर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 818 अंकों तक पहुंच गए हैं। दोनों टीमों के तेज गेंदबाज रैंकिंग में ऊपर चढ़े हैं। भारत के बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्हें धर्मशाला में 13 रन देकर दो विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, चार स्थान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन (14 स्थान ऊपर 25वें स्थान पर) और लुंगी एनगिडी (11 स्थान ऊपर 44वें स्थान पर) ने भी प्रगति की है।

एलेक्स कैरी का शतक, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 326/8

एडिलेड। एलेक्स कैरी (106) की शतकीय और उस्मान ख्वाजा (82) की अर्द्धशतकीय पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे एशेज टेस्ट मैच के पहले दिन बुधवार को स्टैंस के समय आठ विकेट पर 326 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

आज यहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत अच्छी नहीं रही और उसने 33 रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिए। जेक वेदरॉल्ड



(18) और ट्रेविस डे (10) रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन की जोड़ी ने

पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई।

कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 का गाना आज हलचल करेंगे रिलीज



मुंबई। जाने माने अभिनेता और एंकर कपिल शर्मा की फिल्म ह्यकिस किसको प्यार करूं 2 का गाना ‘आजा हलचल करेंगे’ रिलीज हो गया है। किस किसको प्यार करूं 2’ का गाना ‘आजा हलचल करेंगे’ रिलीज हो गया है। ऊर्जा, रोमांस और रंगीन जश्न से भरा यह गीत पहली बार पर्दे पर कपिल शर्मा और त्रिधा चौधरी की ताजा जोड़ी को पेश करता है, जिनकी केमिस्ट्री शरारती, युवा और बेहद सहज अंदाज में दिल जीत लेती है।

अपनी बेहतरीन हास्य टाइमिंग के लिए मशहूर कपिल शर्मा इस गाने में अपनी चुलबुली मौजूदगी से जान डालते हैं, वहीं त्रिधा चौधरी अपनी सादगी, चमक और अपनापन जोड़कर इस जोड़ी को और भी ताजा और देखने लायक बना देती हैं। इस गाने को आवाज गायिका अफसाना खान ने दी है। संगीतकार युग भुसाल ने आधुनिक धुनों को बॉलीवुड के त्योहारों वाले रंग में पिरोकर ऐसा संगीत रचा है, जो गाना खत्म होने के बाद भी

मन में गूंजता रहता है। अजय कुमार के मजेदार और दिल से जुड़े बोल इस जश्न और रोमांस के मूड को खूबसूरती से पूरा करते हैं। फिल्म ह्यकिस किसको प्यार करूं 2’ का पूरा एल्बम अब सभी मंचों पर उपलब्ध है और ह्यआजा हलचल करेंगे’ अपनी सुकून देने वाली ऊर्जा और थिरकने पर मजबूर कर देने वाले अंदाज के लिए श्रोताओं का खूब प्यार बटोर रहा है। यह फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

काजोल ने मनाया कभी खुशी कभी गम के 24 साल का जश्न

मुंबई। बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री काजोल ने अपनी सुपरहिट फिल्म ह्यकभी खुशी कभी गम के 24 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। यश जौहर निर्मित और करण जौहर निर्देशित फिल्म ह्यकभी खुशी कभी गम 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुयी थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने अहम भूमिकायें निभायी थी। फिल्म को प्रदर्शित हुये



24 साल हो गये हैं। निभाया था। काजोल इस फिल्म में काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट साझा की। इसमें अपनी फिल्म ह्यकभी खुशी कभी गम के 24 साल पूरे का

की। इसमें अपनी फिल्म ह्यकभी खुशी कभी गम के 24 साल पूरे का

जश्न मनाया। काजोल ने फिल्म से जुड़ी अपनी एक फोटो शेयर की। काजोल ने यंग लड़कियों को एक खास सलाह दी। काजोल ने कहा, ह्यसभी अंजलियों से कहना चाहती हूं, खुद पर प्राउड फील करो। खुलकर जीयो। राहुल (कभी खुशी कभी गम का लीड कैरेक्टर, जिसे शाहरुख ने निभाया था) ह्यलेट हो सकता है, क्योंकि वह कहीं ट्रैफिक में फंसा होगा ह्य इस मैसेज के जरिए काजोल यंग लड़कियों को खुलकर जीने की सलाह दे रही है।

बाईर 2 दिलजीत ने बाईर 2 के लिए की जीतोड़ मेहनत

मुंबई। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन का कहना है कि फिल्म बाईर 2 के लिए दिलजीत दोसांझ ने काफी कड़ी मेहनत की है। वरुण धवन ने अपनी आने वाली फिल्म बाईर 2 के को-स्टार दिलजीत दोसांझ की जमकर तारीफ की। दोनों कलाकार बहुप्रतीक्षित बाईर 2 में साथ नज आएंगे। फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में इसका



दमदार टीज लॉन्च किया, जिसमें देशभक्ति से भरी कहानी की झलक

देखने को मिली। टीज लॉन्च इवेंट में वरुण धवन मौजूद थे, जबकि दिलजीत

दोसांझ इसमें शामिल नहीं हो सके। इसके बावजूद वरुण ने मंच से दिलजीत

की मेहनत की सराहना की। वरुण ने कहा कि दिलजीत ने फिल्म बाईर 2 के लिए अपना खून-पसीना बहाया है। वह इस फिल्म में पीवीसी का किरदार निभा रहे हैं। मैं उनकी तरफ से भी सभी का धन्यवाद करता हूं। बाईर 2 के टीज में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेटी देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए

क्या सुप्रिया सुले नए साल में बनेंगी मंत्री?

मुंबई: ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को झटका देने और फिर दिल्ली में पार्टी के सांसदों के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में सुप्रिया सुले चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ईवीएम पर स्टैंड बदलने से पहले सुले के केंद्र में मंत्री बनने की अटकलें लग रही हैं, हाल के घटनाओं ने इस अटकलों को और मजबूती दे दी है। सुले ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर उनका दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया था। इतना ही नहीं उधर महाराष्ट्र में लंबे वक्त से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों खेमों के एकजुट होने की अटकलें लंबे समय से लग रही हैं। सिर्फ सुप्रिया और अजित पवार के बीच कड़वाहट कम नहीं हुई, बल्कि रोहित पवार भी अजित पवार के निकट आए हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने पिछले दिनों यह कहकर चौंका दिया था कि वह ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगी, क्योंकि उन्हीं मशीनों



के जरिए वह चार बार सांसद चुनी गई हैं। उनके इस बयान ने हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि उनका यह बयान विपक्षी दलों के रुख से अलग था। सुले ने यह बात लोकसभा में चर्चा के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं उसी मशीन से चुनी गई हूँ, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर

सवाल नहीं उठाऊंगी। राजनीति विशेषकों का कहना है कि इन दिनों जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ और अप्रत्याशित फैसले लिए हैं। उसमें कुछ भी संभव है। अगर सुप्रिया सुले मोदी सरकार में मंत्री बनती हैं तो निश्चित तौर पर यह साल 2026 में बड़ी सियासी घटनाक्रम के तौर पर दर्ज होगी। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के यूपी अध्यक्ष

बनने के मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना प्रबल हुई है। मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ सकते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना बंगाल और दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले जताई जा रही है। राजनीतिक विशेषकों का कहना है कि हाल ही पवार फैमिली में

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों गठबंधन पर फडणवीस का बड़ा बयान

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस ने लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, चुनाव समिति को है, किसी और को नहीं। हमारी भूमिका यह है कि हम महायुति के तहत चुनाव लड़ेंगे। कुछ जगहों पर, जहां यह संभव नहीं है, वहां दोस्ताना लड़ाई है। फडणवीस का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राज्य में तमाम पार्टियों स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले लड़ने की स्थिति के लिए खुद को तैयार करने में जुटी हैं। 2017 के बीएमसी चुनावों में सभी पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ा था। सीएम फडणवीस का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राज्य में निकाय चुनाव का शंखनाद होने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों की मानें तो



राज्य चुनाव आयोग अक्टूबर महीने में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और तीन चरणों में इलेक्शन कराए जाएंगे। पहले चरण में उत्तर और दक्षिण महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की योजना बनाई जा रही है और तीसरे चरण में मुंबई, ठाणे और कोकण में मतदान होगा। चुनाव आयुक्त

दिनेश वाघमारे के अनुसार प्रशासनिक और राजनीतिक योजना के अनुसार 3 चरणों में चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है। इसमें प्रदेश में 29 मनापा, 257 नगर पालिकाओं, 26 जिला परिषदों और 288 पंचायत समितियों के लिए चुनाव अक्टूबर महीने में कराए जा सकते हैं महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त वाघमारे के अनुसार वाडों की संरचना

2011 की जनगणना के अनुसार बनाई जाएगी। कुछ जगहों की संरचना और वार्ड की सीमाओं में बदलाव होगा। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि निकाय चुनाव के लिए एक चरण में 1 लाख 50 हजार ईवीएम मशीनों की जरूरत होगी। आयोग के पास सिर्फ 65 हजार ईवीएम मशीनें हैं। इसलिए आयोग 3 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के घटक दलों को भारी बगावत का खतरा है क्योंकि पार्टियों के गठबंधन में आने पर कम दावेदार ही लड़ सकेंगे। ऐसे में असंतोष बढ़ सकता है। अगर सभी पार्टियों अलग अलग लड़ती हैं तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टियों के लिए जान लगाने वाले नेता अपनी किस्मत आजमा पाएंगे। ऐसे में दोनों ही गठबंधनों के घटक दलों में जहां मुकबला होगा तो वहीं कुछ सीटों पर फ्रंटली फाइट होने की उम्मीद है।

पर्दे के पीछे की बड़ी खबर ! महायुति की 142 सीटें फाइनल



मुंबई: महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई समेत राज्य की 29 म्युनिसिपैलिटी के चुनावों का ऐलान कर दिया। इसके बाद पर्दे के पीछे के राजनीति हलचल ने जोर पकड़ लिया है। महायुति गुट में बड़े डेवलपमेंट चल रहे हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों की तैयारी पिछले कई दिनों से बीजेपी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चल रही थी। चुनावों का ऐलान होते ही अगले ही दिन दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक साथ मीटिंग की और सीट शेयरिंग पर बातचीत की। सूत्रों की खबर है कि इस सीट शेयरिंग में एक अहम फैसला हुआ है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी मुंबई में

मजबूत है। ठाकरे की पार्टी राज ठाकरे की मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। इसलिए बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए बीजेपी को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जरूरत है। इसलिए पता चला है कि आज दोनों पार्टियों के नेताओं की मीटिंग बहुत ही अच्छे से और समझदारी से हुई।

यह भी पता चला है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई टकराव न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसलिए, शिंदे की शिवसेना भी इस चुनाव में मोलभाव की ताकत देख रही है। आइए जानते हैं आज की मीटिंग में क्या हुआ। मुंबई नगर निगम चुनाव के नेताओं की आज एक अहम बैठक हुई। बीजेपी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना

मुंबई नगर निगम चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। लेकिन बीजेपी ने ग्रैंड अलायंस में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपने साथ लेने का विरोध किया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक मुंबई नगर निगम चुनाव को लीड कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने यह स्टैंड लिया है कि वह नवाब मलिक के साथ अलायंस नहीं कर सकती। इसलिए अब बीजेपी और शिवसेना का ग्रैंड अलायंस मुंबई नगर निगम चुनाव साथ मिलकर लड़ेगा दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग में बस एक महीना बाकी है, इसलिए आज शिवसेना और बीजेपी नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर अहम चर्चा हुई। इसमें मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर डिटेल में बातचीत हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में चर्चा है

कि बीजेपी ने शिवसेना को 52 सीटों का प्रपोजल दिया है। लेकिन शिवसेना 125 सीटों की मांग कर रही है। इस पर अगली मीटिंग में बात होगी। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि आज सीट शेयरिंग की पहली मीटिंग में 142 सीटों का झगड़ा सुलझ गया। शिवसेना और बीजेपी के बीच आज हुई बैठक में शिवसेना को 52 और बीजेपी को 90 सीटें देने का फैसला हुआ। लेकिन 85 सीटों का झगड़ा अभी तक नहीं सुलझा है। इसलिए सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन 85 सीटों का झगड़ा सुलझाने के लिए गुरुवार को एक और मीटिंग होगी। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फाइनल सीट शेयरिंग को लेकर फैसला लेंगे।

बीएमसी चुनावों से पहले मुंबईकर को बड़ा गिफ्ट

मुंबई लोकल को 238 ऑटोमैटिक डोर ट्रेनें, फडणवीस का ऐलान



मुंबई: मुंबई बीएमसी चुनावों से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बड़ी गुड न्यूज साझा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय ने बुधवार की देर रात बताया कि मुंबई लोकल ट्रेन के बेड़े में 238 स्वचालित दरवाजा बंद प्रणाली से युक्त नई ट्रेनें खरीदी जाएंगी। फडणवीस ने कहा कि 120 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों और 3200 उपनगरीय लोकल ट्रेनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांद्रा में 3 नई पिट लाइनें विकसित की जाएंगी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर 24-कोच ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस में डिपो का विस्तार

का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के तहत स्वचालित दरवाजा बंद प्रणाली से युक्त 238 नई ट्रेनें खरीदी जाएंगी। 120 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों और 3200 उपनगरीय लोकल ट्रेनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांद्रा में 3 नई पिट लाइनें विकसित की जाएंगी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर 24-कोच ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस में डिपो का विस्तार

होगा। इसके साथ ही कई प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। इनमें जोगेश्वरी में 2, दादर में 1, वसई रोड में 6, पनवेल में 5, कलंबोली में 5, कल्याण में 6 और परेल में 6 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। सीएम फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुंबई में रेल सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। गौरतलब हो कि पिछले कुछ सालों में मुंबई की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक करने के लिए काफी तेज गति से काम हुआ है। मेट्रो नेटवर्क में बढ़ोतरी के साथ कोस्टल ब्रिज, अटल सेतु जैसे बड़े प्रोजेक्टर मुंबईकर को मिले हैं।

मुंबई में फिर बंद हो जाएगी बाइक टैक्सी! परिवहन मंत्री प्रताप सरनार्इक ने ली बैठक

मुंबई: जल्द ही मुंबई में बाइक टैक्सी चलना बंद हो सकती है। क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एग्रीगेटर कंपनियों (ओला, उबर और रैपिडो) को दिया हुआ टेम्पररी बाइक टैक्सी लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। दरसल मुंबई में एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा अनधिकृत तरीके से बाइक टैक्सी चलाई जा रही है। इस वजह से एक महिला यात्री ने अपनी जान भी गवां दी



है, तो वहीं कई यात्री जख्मी भी हुए हैं। यही वजह है कि बुधवार को परिवहन मंत्री प्रताप सरनार्इक ने इस मामले पर बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि स्टेट

ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (रठअ) तीनों कंपनियों को जारी किए गए प्रोविजनल लाइसेंस रद्द करने पर आखिरी फैसला 2 दिनों में लेगी। यह कदम उन घटनाओं के

बाद उठाया गया है, जिनसे बाइक टैक्सी सेफ्टी पर कई सारे सवाल खड़े किये हैं। हाल ही में, कल्याण में एक उबर बाइक टैक्सी सवार ने एक महिला पैसेंजर के

साथ छेड़छाड़ की थी। यही वजह है कि ऐसी घटनाओं ने ऐप-बेस्ड बाइक टैक्सी सर्विस के राइडर वेरिफिकेशन, गाड़ी के नियमों का पालन न करने और रेगुलेटरी निगरानी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट) के अंडर काम करती है, के पास लाइसेंस देने

और कैंसिल करने का कानूनी अधिकार है। सरनार्इक ने एसटीए को रैपिडो, ओला और उबर को दिए गए टेम्पररी लाइसेंस रद्द करने का प्रोसेस शुरू करने के निर्देश दिए। आखिरी फैसला लेने के लिए अथॉरिटी की जल्द ही एक मीटिंग होनी है। अगर लाइसेंस रद्द हो जाते हैं, तो इन एग्रीगेटर्स कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली बाइक टैक्सी सर्विस मुंबई और राज्य के दूसरे

हिस्सों में बंद कर दी जाएगी, जिससे ऐप-बेस्ड टू-व्हीलर टैक्सी ऑपरेशन को झटका लगेगा, जिन्हें पहले भी रेगुलेटरी दिक्कतों का प्रताप सरनार्इक, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बता दें कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पैसेजर्स से अनसेफ राइड्स, अनवेरिफाइड राइडर्स और गैर-कानूनी ऑपरेशन्स के बारे में कई शिकायतें भी मिली हैं। अधिकारी ने कहा कि एनफोर्समेंट टीमों ने कई मौकों

पर कंपनियों को चेतावनी दी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, तीनों कंपनियां बाइक टैक्सी ड्राइवरो का रजिस्ट्रेशन करते समय कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करती हैं। साथ ही, इलेक्ट्रिक बाइक के बजाय पेट्रोल बाइक के जरिए सर्विस जारी रखने के लिए कंपनी के खिलाफ अब तक 36 केस दर्ज किए जा चुके हैं।